Shiv Basant
Chief Secretary to Government

(28)

Government of Jharkhand
Mantralaya, Dhurwa
Ranchi-834 004, India
Tele. : 91-651-2400240/250/627/628
Fax : 91-651-2400255
E-mail : cs-jharkhand@nic.in

D.O. No. 359 /CS

Ranchi, Dated 20th March, 2010

Dear Shri Basu,

Let me first of all congratulate you on assuming charge of one of the most challenging jobs which the Civil Service has to offer.

We are happy that 15 districts of Jharkhand have been included in National Food Security Mission (Pulses) Programme of Ministry of Agriculture, Govt. of India.

Although I know that pulses, oil seeds and horticulture is the comparative advantage of Jharkhand but farmers of the state still love paddy and wheat crop which they are growing since time immemorial. Therefore, I would request you to include 14 districts of Jharkhand namely, Bokaro, Dumka, Garhwa, Palamau, Hazaribagh, Giridih, Sahebganj, Lohardaga, Saraikela, East Singhbhum, West Singhbhum, Dhanbad, Ramgarh and Gumla in National Food Security Mission (Wheat) Programme of Ministry of Agriculture, Govt. of India. Regards,

Yours Sincerely,

(Shiv Basant)

Shri P. K. Basu,
Secretary,
Ministry of Agriculture,
Govt. of India,
New Delhi.

शिबू सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड
3, काँके रोड, राँची-834008
0651-2400233, 2281500 (का.)
☎ 0651-2284241, 2283272 (आ.)
0651-2205100, 2400232 (फै.)

अ०स०प०सं० 3908232
दिनांक 13 मार्च, 2010

प्रिय श्री शरद पवार जी,

झारखंण्ड राज्य के 15 जिलों यथा गुमला, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, राँची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग, पाकुड़, चतरा एवं साहेबगंज में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) स्वीकृत करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

2. यह विदित है कि खाद्यान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ कृषि वर्षा अधारित है अतः मौसम के बदलते मिजाज के कारण खरीफ फसल, विशेषकर धान, के उत्पादन पर अक्सर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में रब्बी फसलों पर विशेष ध्यान देना और भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रदेश की मिट्टी एवं जलवायु गेहूँ की खेती के लिये अनुकूल है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सुनिश्चित सिंचाई सुविधा में भी विस्तार हुआ है।

3. अखिल भारतीय समन्वित सुधार गेहूँ परियोजना अन्तर्गत अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण में गेहूँ की उत्पादकता 40 क्वींटल प्रति हेक्टयर तक पहुँच गई है। अगर झारखण्ड राज्य में भी गेहूँ की उत्पादकता में वृद्धि लायी जाय तो इस फसल का योगदान राजकीय खाद्यान्न भंडार में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। गेहूँ उत्पादन की आधुनिक विज्ञानिक तकनीक इस प्रदेश में उपलब्ध है।

4. अतः मेरा अनुरोध होगा कि राज्य के 14 जिलों यथा बोकारो, दुमका, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज, लोहरदगा, सरायकेला, पू॰ सिंहभूम, प॰ सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और गुमला को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) के अधीन सम्मिलित किया जाय।

झारखंड सरकार

5. इस दिशा में आपके सार्थक सहयोग की अपेक्षा है। आशा है कि आपके द्वारा इस राज्य पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा ताकि खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भरता का लक्ष्य हम शीघ्र प्राप्त कर सकें।

सादर,

भवदीय

(शिबू सोरेन)

श्री शरद पवार,
माननीय मंत्री,
कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण,
भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001.